



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 15 मार्च, 2003/24 फाल्गुन, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

आदेश

शिमला-2, 10 सितम्बर, 2002

संख्या एफ0 एफ0 ई0 बी0 ए0 (3) 4/99. —हिमाचल प्रदेश भू-परिरक्षण अधिनियम, 1978 की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसरण में, राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 15-4/71-एस0 एफ0, दिनांक 19 जनवरी, 1979 द्वारा क्रमशः सोलन जिला की बाबत, 3 फरवरी, 1979 द्वारा चम्बा और बिलामपुर जिलों की बाबत, 6 फरवरी, 1979 द्वारा सिरमौर, शिमला, हमीरपुर और मण्डी जिलों की बाबत, 3 मई, 1979 द्वारा कुल्लू जिला की बाबत, 30 मई, 1979 द्वारा ऊना और कांगड़ा जिलों की बाबत, 27 अगस्त 1980 द्वारा किन्नौर जिला की बाबत अधिसूचनाएं जारी करके निर्देश दिया गया था कि प्रत्येक अनुसूची में दर्शाए गए क्षेत्र में या तो भूमि कटाव है या भूमि कटाव की सम्भावना है और क्षेत्रों पर भूमिगत जल और भूमि कटाव की रोकथाम के लिए इस आदेश में संलग्न अनुसूची में दर्शाए गए क्षेत्रों का परिरक्षण करना अनिवार्य है ; और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन सम्यक जांच के पश्चात् राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि इस आदेश में अन्तरविष्ट विनियम, निर्बन्धन, प्रतिषेध और निर्देश उक्त अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (नगर निगम, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और छावनी बोर्डों की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्रों के

सियाए) इस आदेश के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने से निम्नलिखित कृत्यों को इस आदेश से संचयन अनुसूची में विनिर्दिष्ट हिमाचल प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में 30 वर्षों की अवधि के लिए अस्थायी रूप से विनियमित, निर्बन्धित, प्रतिषिद्ध करते हैं, अर्थात् :—

1. ऐसे क्षेत्रों से वृक्षों या इमारती लकड़ी के कटान (गिरान) और उसका हटाया जाना प्रतिषिद्ध होगा :

परन्तु यह कि चारे और बालन के वास्तविक घरेलू उपयोग के प्रयोजन के लिए काटे (गिराए) जाने वाले वृक्षों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि स्वामी अपने वास्तविक घरेलू और कृषि उपयोग के लिए (चील के वृक्षों के अतिरिक्त) तीन कोनीफरस वृक्ष और चील और अन्य वृक्षों को बाबत प्रत्येक वर्ष 5 वृक्ष बिना अनुमति के और सम्बन्धित परिक्षेत्र अधिकारी की अनुज्ञा से 10 वृक्षों तक और 10 वृक्षों से अनधिक के लिए सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से काट सकेंगे । बांसों की बाबत वास्तविक घरेलू उपयोग के प्रयोजन या उसके अपने कुटीर उद्योग में उपयोग के लिए वृक्ष काटने (गिरान) के लिए वृक्षों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि विक्रय के लिए वृक्षों का कटान (गिरान) दस वर्षों के कटान (गिरान) कार्यक्रम के अनुसार होगा जो कि वन विभाग के अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और निम्नलिखित प्राधिकारियों से अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् वृक्षों को काटा जा सकेगा, अर्थात् :—

वृक्षों की संख्या

वृक्ष काटने (गिराने) अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी

(क) खैर, बांस और अन्य प्रकीर्ण चौड़ी पत्ती की प्रजातियों के लिए :—

वर्ष में 200 वृक्षों तक

सम्बन्धित वन मण्डलाधिकारी

वर्ष में 200 वृक्षों से अधिक

सम्बन्धित अरण्यपाल

(ख) समस्त अन्य प्रजातियों के लिए :—

वर्ष में 50 वृक्षों तक

सम्बन्धित वन मण्डलाधिकारी

वर्ष में 100 वृक्षों तक

सम्बन्धित अरण्यपाल

वर्ष में 200 वृक्षों तक

प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश

वर्ष में 200 वृक्षों से अधिक

हिमाचल प्रदेश सरकार

परन्तु यह और भी कि घरेलू या कृषि उपयोग या विक्रय के लिए वृक्षों को काटने (गिराने) वाले किसी के भी व्यक्ति से काटे (गिराए) गए एक पेड़ के लिए कम से कम तीन वृक्ष समाना अपेक्षित होंगे तथापि ऐसे क्षेत्रों में, फैलीधान लगाए जाने की दशा में इसे बागवानी विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अधिकाधिक प्रमाणों/मानों के अनुसार क्षेत्र के पूर्ण संचयन के लिए लगाया जाएगा ।

इस आदेश के प्रकाशित होने के पश्चात् सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी वृक्षों को काटने (गिराने) का आदेश जारी करेगा :—

परन्तु यह कि बांसों का कटान (गिरान) तीन वर्षीय गिरान कार्यक्रम के अनुसार विनियमित किया जाएगा, जिसे वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बनाया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और विक्रय के लिए बांसों को काटने के लिए अनुज्ञा सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारियों द्वारा तीन वर्षीय गिरान कार्यक्रम के अनुसार दी जाएगी।

3. वृक्ष कटान (गिरान) के लिए अनुज्ञा क्षेत्रों से आने वाली वन उपज, किसी भी वन अधिकारी द्वारा जांची जा सकेगी और कोई भी वन उपज, किसी व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी से अभिप्राप्त, निर्यात पास अभिप्राप्त किए बिना बाहर नहीं निकाली जाएगी।

4. वृक्ष कटान (गिरान) के लिए अनुज्ञा प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी, अनुज्ञा प्रदान करते समय ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जैसी वह वन अनुरक्षण के हित और इस प्रकार बाहर निकाली गई वन उपज के दुरुपयोग से बचने में, अनिवार्य समझे।

5. पूर्वगामी पैरों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अध्वधीन रहते हुए जैसी अधिरोपित करना या वृक्ष की श्रेणी वह उचित समझे, किसी वृक्ष का कटान (गिरान) या हटाना अनुज्ञात कर सकेगी। जहां कहीं निम्नलिखित प्रयोजन के लिए लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, अर्थात् :—

- (क) नौतोड़ भूमि का अनुदान; या
- (ख) धृतियों की चकबन्दी; या
- (ग) सूखे/गिरे हुए वृक्ष।

6. विहित वर्ष के भीतर वृक्ष न काटने की दशा में, प्रधान मुख्य अरण्यपाल निम्नलिखित परिस्थितियों में उस अवधि को बढ़ा सकेगा :—

- (i) जहां भूमि का सीमांकन और वृक्षों के अंकन की प्रक्रिया, वृक्ष कटान (गिरान) के विहित वर्ष के दौरान पूर्ण हो गई हो और वृक्ष कटान (गिरान) आदेश, सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं, लेकिन वृक्ष कटान (गिरान) नहीं किया गया है या भागतः किया गया है; और
- (ii) जहां भूमि का सीमांकन और वृक्षों के अंकन की प्रक्रिया वृक्ष कटान के विहित वर्ष के दौरान पूर्ण हो गई है लेकिन वृक्ष कटान (गिरान) आदेश जारी नहीं किए हैं।

स्पष्टीकरण.—“विहित वर्ष” से वह वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है जिसमें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित 10 वर्षीय कटान (गिरान) कार्यक्रम के अनुसार विशिष्ट क्षेत्र की बाबत वृक्ष काटे (गिराए) जाने हैं।

7. इस आदेश के पैरा 6 के उप-पैरा (i) और (ii) वर्णित से अन्यथा समस्त अन्य मामलों में, वृक्ष काटने (गिराने) की अनुज्ञा प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्र के अनुमोदित 10 वर्षीय वृक्ष कटान कार्यक्रम की दृष्टि में लाए बिना, निम्नलिखित परिस्थितियों में वृक्ष कटान (गिरान) की मंजूरी दे सकेगा, अर्थात् :—

(i) जहां वृक्ष गिर गए हैं या प्राकृतिक आपदा, बिमारी या कीट आक्रमण इत्यादि के कारण सूख गए हैं और उनके रखने से मूल्य में हानि (कमी) होगी ;

(ii) जहां, विशिष्ट राजस्व संपन्नाओं में भूमि धृति चकबन्दी प्रवर्तन के अधीन है, वहां उनसे आने वाले वर्ष, जिसमें ये प्रवर्तन समाप्त हुए हैं वृक्ष कटान का विहित वर्ष समाप्त जाएगा ;

- (iii) जहाँ सरकारी/प्राइवेट भूमि लोक प्रयोजन, जैसे कि अवसंरचना प्रसुविधाओं के सृजन या सिंचाई और जलापूर्ति लाईनों या पारेषण लाईनों अथवा प्रवहण पद्धति बिठाना या उद्योग, हाईड्रो पावर प्रोजेक्ट (जल विद्युत परियोजनाएं) पर्यटन स्थल या शैक्षणिक संस्थाओं अथवा अन्य कोई प्रसुविधाएं प्रदान करना जो लोक हित में है; के लिए अर्जित या पट्टे पर दी गई है या कथ अथवा अन्तरित की गई है; और
- (iv) जहाँ गैर वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि का अपयोजन के लिए भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

8. सभी मामलों में (इस आदेश के पैरा 6 और 7 में वर्णित से अन्यथा) जहाँ, अनुमोदित 10 वर्षीय वृक्ष कटान (गिरान) कार्यक्रम के अनुसार विहित वर्ष के दौरान भूमि का सीमांकन और वृक्षों का अंकन नहीं किया गया है, तो वहाँ के सीमांकन, वृक्षों के अंकन और कटान की अनुज्ञा, वृक्ष कटान के विहित वर्ष के पश्चात् भी निम्नलिखित द्वारा दी जा सकेगी ;

- (i) एक वर्ष तक प्रधान मुख्य अरण्यपाल; और
- (ii) दो वर्ष तक राज्य सरकार द्वारा; यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान है।

9. जहाँ, इस आदेश के पैरा 8 के अधीन अनुज्ञा दी गई है तो वहाँ, सम्बद्ध वन मण्डलाधिकारी, भूमि सीमांकन और वृक्षों का अंकन करने के पश्चात् वृक्ष कटान (गिरान) का आदेश जारी करेगा।

10. भूमि के सीमांकन के लिए आवेदन जिससे वृक्षों का कटान (गिरान) प्रस्तावित है सम्बद्ध वन मण्डलाधिकारी के समक्ष कटान की विहित तारीख से एक वर्ष अग्रिम में दाखिल की जा सकेगी और सम्बद्ध वन मण्डलाधिकारी भूमि के सीमांकन के लिए मामले में कार्यवाही कर सकेगा।

11. अनुमोदित 10 वर्षीय कटान कार्यक्रम में यथानियत किसी भी दशा में विहित वर्ष से पूर्व वृक्षों के कटान (गिरान) की अग्रिम में अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

12. कटान (गिरान) के विहित वर्ष के भीतर प्राइवेट क्षेत्रों से वृक्षों के कटान (गिरान) और निष्कर्ष की पूरा करने के लिए और बार-बार विस्तार न लेने के लिए विस्तारण फीस शेष वृक्षों के कटान (गिरान) परिमाण (वाल्यूम) की संख्या के लिए निम्नलिखित दर पर उद्गृहीत की जाएगी :—

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. राष्ट्रीयकृत प्रजाति | रुपये 100 प्रति घन मीटर (खण्ड वृक्ष) |
| 2. खैर | रुपये 30 प्रति मीटर गर्थ |
| 3. चौड़ी पत्ती वाली प्रजाति | रुपये 10 घन मीटर |

अनुसूची

क्रम संख्या	जिला	धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्या और तारीख	तहसील	गांव
1	2	3	4	5
1.	सोलन	संख्या 15-4/71-एस0 एक0, 19 जनवरी, 1979.	1. सोलन 2. कण्डाघाट 3. अर्की 4. नालागढ़ 5. कसौली	इन तहसीलों में सम्पूर्ण प्राइवेट क्षेत्र।

2	3	4	5
चम्बा	संख्या 15-4/71-एस0 एफ0, 3 फरवरी, 1979.	1. चम्बा 2. चुराह 3. डलहौजी 4. पांगी 5. भरमौर 6. सलूणी 7. भटियात	इन तहसीलों में सम्पूर्ण प्राईवेट क्षेत्र।
विलासपुर	संख्या 15-4/71-एस0 एफ0, 3 फरवरी, 1979.	1. घुमारवीं 2. विलासपुर 3. झण्डूता	इन तहसीलों में सम्पूर्ण प्राईवेट क्षेत्र।
सिरमौर	संख्या 15-4/71-एस0 एफ0, 6 फरवरी, 1979.	1. नाहन 2. पांवटा 3. संगडाह 4. राजगढ़ 5. शिलाई 6. पच्छाद	इन तहसीलों में सम्पूर्ण प्राईवेट क्षेत्र।
शिमला	संख्या 15-4/71-एस0 एफ0, 6 फरवरी, 1979.	1. शिमला (शहर) इन तहसीलों में 2. शिमला (ग्रामीण) सम्पूर्ण प्राईवेट क्षेत्र। 3. सुन्नी 4. ठियोग 5. कुमारसैन 6. रामपुर 7. चौपाल 8. कोटखाई 9. जुब्बल 10. रोहडू 11. चिड़गांव 12. डोडराक्वार	
हमीरपुर	संख्या 15-4/71-एस0 एफ0, 6 फरवरी, 1979.	1. हमीरपुर 2. बडसर 3. नदौन 4. भोरंज 5. सुजानपुर टीहरा	इन तहसीलों में सम्पूर्ण प्राईवेट क्षेत्र।
मण्डी	संख्या 15-4/71-एस0 एफ0, 6 फरवरी, 1979.	1. मण्डी (सदर) इन तहसीलों में 2. सुन्दरनगर सम्पूर्ण प्राईवेट क्षेत्र। 3. जोगिन्दरनगर 4. सरकाघाट 5. करसोग 6. थुनाग 7. चच्योट (गोहर) 8. पधर 9. लडभडोल	

1	2	3	4	5
8.	कुल्लू	संख्या 15-4/71-एस0 एफ0, 3 मई, 1979.	1. कुल्लू 2. बन्जार 3. मनाली 4. निरमण्ड	इन तहसीलों में सम्पूर्ण प्राईवेट क्षेत्र।
9.	ऊना	संख्या 15-4/71-एस0 एफ0, 30 मई, 1979.	1. अम्ब 2. बन्नाणा 3. ऊना	इन तहसीलों में सम्पूर्ण प्राईवेट क्षेत्र।
10.	कांगड़ा	संख्या 15-4/71-एस0 एफ0 30 मई, 1979.	1. कांगड़ा 2. धर्मशाला 3. देहरा 4. नूरपुर 5. ज्वाली 6. इन्दौरा 7. जयसिंहपुर 8. पालमपुर 9. बैजनाथ 10. शाहपुर 11. बडोह 12. जस्वां कोटला 13. खुण्डियां 14. फतेहपुर	इन तहसीलों में सम्पूर्ण प्राईवेट क्षेत्र।
11.	किन्नोर	संख्या 15-4/71-एस0 एफ0, 27 अगस्त, 1980.	1. कल्पा 2. निचार 3. मुरंग 4. पहा 5. सांगला	इन तहसीलों में सम्पूर्ण प्राईवेट क्षेत्र

यह आदेश राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण), तारीख 28 अप्रैल, 1979, 13 सितम्बर, 1980 और 12 मार्च, 1981 को क्रमशः प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या 15-4/71-एस0 एफ0, तारीख 13 मार्च, 1979, 27 अगस्त, 1980 और 25 फरवरी, 1981 और उस बारे किए गए समस्त संशोधनों का अधिग्रहण करता है।

आदेश द्वारा;

अभय शुक्ला;
प्रधान सचिव।